शब्द–ब्रह्म
ISSN 2320 – 0871
भारतीय भाषाओं की अंतर्राष्ट्रीय मासिक शोध पत्रिका
17 दिसम्बर 2014
पीअर रीव्यूड रिसर्च जर्नल

सम्पादकीय

नेशनल प्लानिंग का अर्थ विलेज प्लानिंग हो

स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने लालकिले से भाषण देते हुए योजना आयोग को समाप्त कर उसके स्थान पर नयी व्यवस्था करने की घोषणा की थी। इसी तारतम्य में गत 7 दिसंबर को श्री मोदी जी ने प्रदेश के मुख्यमंत्रियों के साथ दिल्ली में बैठक आयोजित की। राजनीतिक कारणों से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री सुश्री ममता बैनर्जी और जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री श्री उमर अब्दुल्ला बैठक में सम्मिलित नहीं हुए। भारत के समग्र विकास की दृष्टि से योजना आयोग बनाया गया। लेकिन योजना आयोग की प्राथमिकता कभी भी इस देश के अंतिम व्यक्ति का विकास नहीं रहा। उसकी नजर में ग्रामीण भारत प्रायः ओझल रहा। आज भी योजना आयोग को लेकर भ्रम की स्थिति है।

योजना आयोग पर विनोबा ने अनेक टिप्पणियां की हैं। भारत सरकार की आर्थिक नियोजन समिति प्लानिंग कमीशन के सदस्य श्री रा.कृ.पाटिल के साथ 10 अगस्त 1951 को ब्राह्म विद्या मंदिर पवनार में चर्चा हुई। जिसमें विनोबा जी ने सबसे पहले रोजगार की बात रखी। विनोबा कहते हैं, "मैं पहले सबको काम और अन्न दूंगा, सारी योजना उस दृष्टि से तैयार करूंगा। लोग कहेंगे,यह पद्धति अच्छी नहीं है, रद्दी है, जंगली है। मैं मानता हूं कि मेरी पद्धति रद्दी है, जंगली है, लेकिन इस तरीके के भरोसे हम सब जी सकते हैं। आज हमें जीने दीजिए, फिर आगे चलकर हम अपनी योजना में सुधार करेंगे। सबको काम देने के बारे में आपको ऐसी प्रतिज्ञा करनी चाहिए कि अमुक तारीख से हम सबको काम देंगे। आप ऐसी प्रतिज्ञा कीजिए और फिर चाहे जैसा संयोजन कीजिए।...परंतु आप उलटे कहते हैं कि सबको काम देना संभव नहीं है। सारे राष्ट्र को काम देने की जिन पर जिम्मेदारी है, उन्हें अगर यह संभव नहीं मालूम होता, तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। आज देश में बेरोजगारी सबसे बड़ा संकट है। देश में जनसंख्या नियंत्रण के प्रश्न पर भी आपस में मतभेद हैं। राजनीतिक दल इस प्रश्न को धर्म से जोड़कर जटिल बना देते हैं। इस बारे में विनोबा ने चर्चा करते हुए कहा कि मेरे भरे हुए घर के बारे में ऐसा कहने वाले आप होते कौन हैं ? आप हमारे सेवक हैं या गुरु ? आपका काम हमें खिलाने का है। हिंदुस्तान में प्रजा ज्यादा है, ऐसा मैं नहीं मानता। यह प्रश्न संतान निरोध का नहीं है वरन् जीवन-परिवर्तन का और उसके अनुकूल परिस्थिति निर्माण करने का है। श्री मोदी जी ने पिछले दिनों लोगों से एक वस्त्र खादी का पहनने की बात कही। उसका असर लोगों पर होता दिखाई दिया। खादी ग्रामोद्योग के प्रश्न पर विनोबा जी ने श्री पाटिल जी से चर्चा करते हुए कहा ग्रामोद्योगों से आप कहते हैं कि वे अपने पैरों पर खड़े रहें। आप मेरी टांगे तोड़ देते हैं और फिर मुझसे अपनी टांगों पर खड़े रहने के लिए कहते हैं!...आपको सोचना चाहिए कि गांधी जैसा अकेला आदमी अगर विषम परिस्थिति में इतना कर सका, तो आज जबकि अपनी सरकार है, कितना अधिक होना चाहिए ?...आप यह कबूल कीजिए कि हम सबको काम देंगे। फिर आप देखेंगे कि ग्रामोद्योग के सिवा मार्ग ही नहीं है। अन्न स्वावलंबन के बारे में भी देश में एक भ्रम कायम किया गया है। पिछले सालों में हमें गेहूं का आयात करना पड़ा। पाम आइल हम आज तक आयात कर रहे हैं। विनोबा ने अन्न के मामले में बुनियादी सवाल उठाते हुए प्रश्न किया कि अन्न का अभाव होने

पर आप क्या करेंगे ? कल अगर पाकिस्तान से आपकी लड़ाई हो गयी तो साफ है कि वे आपको अनाज देने से इनकार करेंगे। फिर अमेरिका वगैरह जो कोई आपको अनाज देंगे,वे आपके लिए प्रेम के कारण देंगे या आपको अपने बंधनों में बांधने के लिए देंगे ? इसलिए आप कम-से-कम इतना क्यों नहीं करते कि अन्न और वस्त्र के बारे में हमें स्वावलंबन साधना है।

विनोबा ने तो योजना आयोग की रिपोर्ट को मूर्खतापूर्ण ही घोषित किया। पहली पंचवर्षीय योजना से लगाकर अब तक चली आयी योजनाओं में गांव को कभी ध्यान में रखा ही नहीं गया। इस बारे में विनोबा कहते हैं देहात के जो धंधे आपने छीन लिए हैं, वे आप देहातियों को वापस नहीं देते।...आपने देहातियों से कपड़े का धंधा छीन लिया और मिलें खोलीं, तेल का धंधा छीन लिया, तेल की मिलें खोलीं। गुड़ का धंधा छीनकर शकर के कारखाने खोले। इस तरह देहातों को कंगाल बनाने के बाद अगर वे देहाती आप पर चढ़ाई करते हैं तो उस चढ़ाई के सामने आप कैसे टिक सकेंगे ? शहरवालों का रक्षण तब आप कैसे कर सकेंगे ? इसलिए ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए जिससे ग्राम के उद्योगों का नुकसान हो। इस विषय में हमारा सिद्धांत यह है कि जिन धंधों का कच्चा माल देहातों में पैदा होता है और जिनके पक्के माल की देहात के लोगों को जरूरत होती है, वे धंधे देहातियों के लिए रिजर्व्ड यानी सुरक्षित रखने चाहिए। सुरक्षित जंगलों की तरह कुछ धंधे भी देहातियों के लिए सुरक्षित क्यों नहीं रखे जा सकते ?

योजना आयोग की रिपोर्ट में कहा गया कि कसाईखानों का भी पशुसंख्या पर कोई परिणाम नहीं हुआ है। आजादी के बाद से अब तक देश में कतलखानों की संख्या में निरंतर वृद्धि हुई है। योजना आयोग ने तो यहां तक कहा कि देश के पशुधन का मांस निर्यात करके विदेशी मुद्रा कमाई जा सकती है। विनोबा ने गोहत्या-बंदी को लेकर सीधा प्रश्न किया कि आपको अपने देश का रक्षण करना है या नहीं ? यदि करना है तो गोवध भारतीय संस्कृति को अनुकूल नहीं आता, इसका आपको ध्यान रखना चाहिए! गोहत्या जारी रही तो हिंदुस्तान में बगावत होगी, इसलिए गोहत्या जारी रहे, कहने की हिम्मत आपको नहीं होती। संतान-निरोध के बारे में आप स्पष्ट बोलते हैं। शराब-बंदी के बारे में धीरे चलो का आग्रह रखते हैं। उसी तरह यह भी कह डालिए कि गाय मारने में कोई हर्ज नहीं! क्या आप ऐसा नहीं मानते कि गोहत्या बंदी हिंदुस्तान के लोगों का मेंडेट है ? आपको निःसंदिग्धरूप से कहना चाहिए कि हम गोहत्या-बंदी करेंगे।

पाटिल जी ने प्रश्न किया कि जमीन का बंटवारा किस तरह करें ? जब विनोबा ने भूदान का विचार समझाया तो पाटिल जी ने कहा कि यह सब आज मुमकिन नहीं मालूम होता। तब विनोबा का कहना था मुमकिन होना चाहिए। मुझे उसी की जल्दी है। जमीनें जल्दी बांट दी जानी चाहिए। इस मामले में जो कुछ आप कर सकें, कीजिए। बाकी रहा हुआ काम मेरा है। तब पाटिल जी ने कहा जमीन भी तो काफी नहीं है ? तब विनोबा को कहना पड़ा कि जमीन काफी नहीं है, अन्न काफी नहीं है, वस्त्र काफी नहीं है।...पाटिल जी ने कहा खादी के जरिये देश की कपड़े की जरूरत पूरी करने का इरादा करें तो भी वह दस साल में मुमकिन होगा, ऐसा नहीं लगता। विनोबा बोले, "मैं दो साल में सारे देश में खादी-ही-खादी करके दिखाता हूं। यह न हो तो मुझे फांसी पर लटका दीजिए। लेकिन आपको खादी करनी ही न हो तो बात अलग है।

पाटिल जी ने कहा कि आप कहते हैं सबको काम देना चाहिए आज यह कैसे हो सकता है ? विनोबा ने कहा क्यों नहीं हो सकता ? फिर आपने गांव के लोगों को वैसी सिफारिश किस आधार पर की है ? गांव को एक राज्य समझना चाहिए। मैं सौ में से दस आदमियों से हाथ से

शब्द–ब्रह्म
ISSN 2320 – 0871
भारतीय भाषाओं की अंतर्राष्ट्रीय मासिक शोध पत्रिका
17 दिसम्बर 2014
पीअर रीव्यूड रिसर्च जर्नल

खेती करने को कहूंगा। प्रायः बेकारी उतनी ही होती है। और जरूरत होगी तो उन्हें ग्रामोद्योग दूंगा। खेती और ग्रामोद्योगों के बल पर गांव की बेकारी दूर की जा सकती है। मैं प्रत्येक गांव में सब गांववालों के जिसमें हिस्से हों, ऐसी एक सहकारी दूकान खोलूंगा। उस दूकान से मुझे पता चलेगा कि गांव को किस माल की कितनी जरूरत होती है। फिर वे उद्योग उस गांव में शुरू किए जा सकेंगे।

सन् 1964 में योजना आयोग के सदस्य श्री श्रीमन्नारायण और श्री अशोक मेहता पवनार विनोबाजी से मिलने गए। तब विनोबा ने प्रश्न किया कि, "आप लोग सब लोगों की न्यूनतम आवश्यकताएं कब पूरी कर सकेंगे ? इस पर अशोक मेहता ने कहा था, 'सन् 1980 तक हमे उसकी शक्यता नहीं दीखती।' तब विनोबा ने कहा, 'आप और 16 वर्ष तक राज्य करते रहेंगे, इसका क्या भरोसा ? कौन कह सकता है कि उस समय विश्व और भारत की स्थिति कैसी रहेगी ? आज जो सुखी हैं उन्हें अधिक सुखी बनाने में क्या तुक है ? आज जो डूब रहा है, उसे तुरंत आधार जरूरी है। उसे कल का दिन भी बताकर काम नहीं चल सकता।...विनोबा जी ने योजना वालों से पूछा कि जो सबसे गरीब है, योजना में उनके लिए क्या विशेष प्रबंध है ? योजना से सारे देश का जीवनमान कुछ बढ़ेगा, यह ठीक है, लेकिन गरीब के जीवनमान में क्या फर्क होगा ? उन्होंने समझाया कि सबका स्तर बढ़ेगा तो नीचे वालों का भी कुछ स्तर बढ़ेगा। विनोबा ने इसे थियरी आफ परकोलेशन नाम दिया। ...भारत की औसत आय बढ़ने पर भी गरीब को कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि उसका जो लाभ है, वह उपर वालों को मिल जाएगा और नीचेवाले उससे वंचित रह जाएंगे। भारत में आज ऐसा होता दिखाई दे रहा है।

जब विनोबा के पास दूसरी पंचवर्षीय योजना की नकल आई तो विनोबा ने यही कहा कि इसकी भाषा वे समझ नहीं पाए। तब पूछा गया कौन सी भाषा ? विनोबा ने कहा, 'बापू ने कहा था कि कस्तूरबा ट्रस्ट का काम उन गांवों में चलना चाहिए, जहां जनसंख्या दो हजार से नीचे हो। क्या शहरवालों से बापू का द्वेष था? जो सबसे दुःखी अवयव है, उसके पास पहले मदद पहुंचनी चाहिए। इसलिए विनोबा ने कहा कि पंचवार्षिक योजना में यह बात होती कि इतनी सारी रकम ऐसे छोटे-छोटे गांवों के लिए खर्च हो रही है, तब तो वह भाषा समझ सकते थे।...पैसा खर्च हो रहा है लेकिन नीचे नहीं पहुंच रहा है। बीच में ही खत्म हो रहा है।...दो पंचवर्षीय योजनाओं पर अरबों रुपये खर्च हुए। फिर भी यह सत्य है कि नीचे के तबके को मदद नहीं पहुची। यह समझना चाहिए कि योजना जिस पद्धति द्वारा हो रही है, उस पद्धति में दोष है।....सबको काम सबको रोटी हमारा मूलभूत सिद्धांत होना चाहिए, क्योंकि वह बुनियादी बात है।

विनोबा ने कहा कि योजना को लेकर उनका अभिप्राय पूछा जाए तो इसका पता होना चाहिए कि गांवों के लिए, नीचे के स्तर के लिए कितना खर्च होने वाला है ? ...मिसाल के तौर पर क्या प्लानिंग में मेहतरों की मुक्ति की योजना की गयी है ? अगर नहीं है, तो प्लानिंग कमीशन की योजना इस दृष्टि से निकम्मी है। योजना ऐसी होनी चाहिए कि प्लानिंग का फलाना हिस्सा किसके लिए है, यह साफ-साफ कहा जाना चाहिए। सड़क बनाने की योजना सबके लिए है। अमीर-गरीब दोनों के लिए सड़क काम आती है। लेकिन आज की हालत में वह गरीबों को मदद पहुंचाने की योजना नहीं हो सकती। जब तक गांवों में ग्रामोद्योग न चलें और गांव के कच्चे माल का वहीं पक्का माल न बने, तब तक ये रास्ते उनके लिए वरदान नहीं, अभिशाप ही बनेंगे। जो शोषक व्यापारी उनका शोषण करने वहां तक नहीं आ पाते थे, वे भी वहां पहुंच जाएंगे।...गांव-गांव को उसकी बुनियादी

शब्द–ब्रह्म
ISSN 2320 – 0871
भारतीय भाषाओं की अंतर्राष्ट्रीय मासिक शोध पत्रिका
17 दिसम्बर 2014
पीअर रीव्यूड रिसर्च जर्नल

आवश्यकताओं के लिए उसकी अंतर्गत शक्ति से स्वावलंबी बनाना देश को खतरे से बचाने के लिए जरूरी है।

विनोबा कहते हैं आज देश की योजना दिल्ली वाले करते हैं। प्लानिंग करते समय पहली बात यह मानी जाती है कि बेकारी कम होगी। लेकिन इसका नतीजा उलटा आ रहा है। यह योजना असल में परदेश की योजना है। क्योंकि योजना बनाने वालों के दिमाग विदेशी विचारों से भरे हैं। यहां लाखों देहात, रहने वाले करोड़ों आदमी और उनके करोड़ों हाथ, इस तरफ उनका कोई ध्यान नहीं जाता। ये सेवक दिल्ली मे सेवकालय - सचिवालय में बैठते हैं और वहीं से गांवों की सेवा कैसे की जाए, यह तय कर डालते हैं।....दिल्ली में बैठकर गांवों की योजना करेंगे तो कैसे चलेगा ? गांवों की सेवा गांवो की मर्जी से ही होनी चाहिए। दिल्ली की योजना देहात में नही चल सकती।...हर एक गांव को यह हक हो कि उस गांव में बाहर से कौन-सी चीज आए और कौन-सी न आए, इसका निर्णय वह कर सके। अगर कोई गांव चाहता है कि उस गांव में कोल्हू चले और मिल का तेल न आए, तो मिल का तेल रोकने का हक उसे होना चाहिए। गांव में नियंत्रण की सत्ता हो। इसलिए राष्ट्रीय नियोजन के बजाए 'विलेज प्लानिंग' (गांव का नियोजन) होना चाहिए। 'बजाय' मैंने कह दिया पर बेहतर तो कहना यह होगा कि नेशनल प्लानिंग का ही अर्थ विलेज प्लानिंग हो। इस विलेज प्लानिंग के लिए और जो कुछ करना पड़े, उतना दिल्ली में किया जाए।

हरएक को एक पौंड आधा लीटर दूध, तीस तोला अनाज आधा किलो अनाज, एक औंस 30 ग्राम घी या तेल, 30 ग्राम गुड, आधा किलो तरकारी मिलना चाहिए। यह आहार का औसत प्रमाण है। प्रत्येक को 18 मीटर कपड़ा चाहिए, तालीम का अच्छा इंतजाम होना चाहिए, बीमारी के लिए दवा का प्रबंध होना चाहिए। काम करने के लिए औजार, रहने के लिए अच्छा-सा घर, मनोरंजन के लिए निर्दोष पर्याप्त साधन चाहिए और आठ घंटे से अधिक काम नहीं चाहिए। ग्रामसभा को इस अंदाज से पूरी योजना बनानी चाहिए।

सरकार गांवों को मदद करे, लेकिन योजना गांव के लोगों की बनायी हुई होनी चाहिए। हमारी निर्दोष योजना लादने की अपेक्षा गांववालों को गलत प्रयोग करने की आजादी देनी चाहिए। गांधीजी ने स्वराज्य की व्याख्या करते हुए कहा था कि स्वराज्य यानी गलतियां करने का हक। सरकारी प्लानिंग ग्रामदान के सिद्धांत पर ही खड़ा होना चाहिए। इसमें थोड़ा-सा कोअर्शन (दबाव) का अंश आ जाए तो भी हर्ज नहीं। आज हिंदुस्तान की क्या हालत है ? सारा काम तो मजदूर करेंगे। लेकिन योजना बनाते समय उनसे कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। खेत में क्या बोना है, यह क्या कभी बैल से पूछा जाता है ? मजदूरों के बारे में भी ऐसा ही सोचते हैं।....इससे समाज को लाभ नहीं होगा। समाज में असंतोष बढ़ेगा, काम अच्छा नहीं होगा। काम में मजदूर का हिस्सा ज्यादा रहेगा और अनाज पर उसका कोई अधिकार नहीं रहेगा। इसलिए मालिक को अनाज हजम नहीं होता।

आज एक बार फिर देश के सामने यह सवाल उपस्थित हुआ है कि आखिर हमारी योजना में कहां गलतियां रह गई। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने योजना आयोग को समाप्त करने की घोषणा तो कर दी, परंतु उनके सामने कोई विकल्प उपस्थित नहीं है। वे इस संबंध में मुख्यमंत्रियों से लगाकर देश के बुद्धिजीवियों से चर्चा कर रहे हैं। देश की योजना को लेकर विनोबा की दृष्टि बिलकुल साफ है। आज देश की सरकार ने जिन पैमानों के आधार पर विकास को परिभाषित किया है, उसे पूरी तरह बदले बिना देश का उद्धार नहीं होगा। इस देश की योजना बनाने में 6 लाख 36 हजार गांवों को शामिल करना सर्वोत्तम होगा।

- पुष्पेन्द्र दुबे